

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 21 मार्च, 2007

विषय: जिला नैनीताल में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के शासकीय कार्य हेतु निजी भवन स्वामियों से किराये पर लिये गये भवन के किराये के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 281/नौ-हे०ना०/2006, दिनांक 5.2.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला नैनीताल में न्यायिक अधिकारियों के अध्यासन हेतु निजी भवन स्वामी से किराये पर लिये गये आवासीय भवन के माह अगस्त, 05 से अप्रैल, 06 तक रुपये 5000/- प्रति माह की दर से कुल रुपये 45,000/- के किराये में से अवशेष धनराशि रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) को व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (I) बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों तथा शासन के अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय ।
- (II) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जाय ।
- (III) निजी व्यक्तियों से किराये पर लिये गये भवनों के किराये का भुगतान नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् किया जाय ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के लिए अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-सिविल और सेशन न्यायाधीश-00-17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या: 105-दो(1)/XXXVI(1)/2006-604/01-तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश, नैनीताल ।
3. श्री राजीव कुमार खुल्बे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
5. वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(एम०एम०समवाल)
अनु सचिव ।